

ख0न0 175 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज है। उत्तर दिशा में ख0न0 175 की कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 15 के नाम खातेदारी में दर्ज है। दक्षिण दिशा में ख0न0 175 अप्रार्थी संख्या 16 लगायत 20 के खातेदारों के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का राजस्व रिकार्ड में विधिक रूप से नक्शा ट्रेस में मौके पर काबिज अनुसार तरमीम हो रखी है तथा प्रार्थीगण ही मौके पर अपनी खातेदारी की उक्त भूमि पर काबिज होकर उपयोग, उपभोग करते चले आ रहे हैं प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवाने के तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा आदेश हल्का पटवारी व गिरदावर के नाम जारी किया गया तत्पश्चात सीमाज्ञान किया गया। प्रार्थीगण व पड़ोसी खातेदारान् अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 20 के मध्य आये दिन सीव को लेकर विवाद करते रहते हैं एवं प्रार्थीगण को बिना किसी वजह से काश्त करने में बाधा रूकावट कारित करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को काफी परेशानी होती है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख0न0 174 की पत्थरगढ़ी करवाया जाना अति आवश्यक है अन्यथा वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिल सकता है। प्रार्थीगण निर्बाध रूप से संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि पर सीमाज्ञान मौका रिपोर्ट 27.12.2023 के बनाने के बावजूद विवाद होने के कारण प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी संख्या 8 की मृत्यु होने के कारण 8/1 लगायत 8/9 को भूमिधारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। प्रार्थी की ओर से निवेदन है कि वाद वर्णित संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौक करवा कर सीमाज्ञान करवा कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिलशुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 से 17, 19, 20 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) पेश किया जिसको स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 18 को डिलीट किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 21 तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की वाद वर्णित भूमि व इससे लगवा पड़ोसी खातेदारान के मध्य नीव सीव के संबंध में विवाद होता रहता है इसलिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है ताकि वाद बाहुल्यता ना बढ़े। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें। पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ ने अपनी बहस में पैरोकार सरकार के जवाब को ही बहस माने जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम रघुनाथपुरा के ख0न0 174 क्षेत्रफल 0.5905 है0 भूमि की पड़ोसी खातेदारो को सूचित करते हुये उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने के आदेश दिये जाते हैं। इस हेतु तहसीलदार रूपनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क की राशि रूपये 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये मात्र नियत की जाती है। जिसका मौके पर भुगतान हो। पत्थरगढ़ी शुल्क की राशि रूपये 100/- अक्षरे एक सौ रूपये मात्र जरिये चालान जमा होने पर आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।



रामकुमार अड्डा
(अ.स.ए.ए.स.)
सहायक उपखण्ड अधिकारी एवं
रूपनगढ़ (अजमेर)